International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN:2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 04(I), October-December, 2026, pp. 119-126

भारत में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का विकास और राजनीतिक विश्वासः बिहार के विशेष संदर्भ में एक वर्णनात्मक अध्ययन

जुसी रानी[1*] | डॉ. मो. इंतखाब आलम[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार।
[2]सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एस. एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद, बिहार।

[*]Corresponding Author: satyavirkumar243@gmail.com

Citation: रानी, जुसी एवं आलम, इंतखाब (2026). भारत में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का विकास और राजनीतिक विश्वासः बिहार के विशेष संदर्भ में एक वर्णनात्मक अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(04(I)), 119–126. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.4(I).9657

सार

यह लेख भारत में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के विकास–क्रम और राजनीतिक विश्वास की अवधारणा के संबंध का वर्णनात्मक विवेचन करता है और बिहार तथा नालंदा जिले को उस व्यापक चित्र के भीतर रखता है। यह द्वितीयक साहित्य तथा सरकारी एवं संस्थागत आँकड़ों पर आधारित है; इसमें कोई प्राथमिक सर्वेक्षण–आँकड़ा प्रस्तुत नहीं है। लेख के तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, पिछले दो दशकों में कल्याण योजनाएँ श्अधिकार–आधारितश कानूनों (मनरेगा 2005, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) से बढ़कर डिजिटल, प्रत्यक्ष हस्तांतरण–आधारित और केंद्र–ब्रांडेड योजनाओं की ओर गई हैं, और 2025–26 में मनरेगा का स्थान नए कानून ने लिया है। दूसरा, उपलब्ध अध्ययन बताते हैं कि लाभार्थी योजना का श्रेय किसे देते हैं और लाभ कितनी सहजता से मिलता है, ये दोनों बातें राजनीतिक प्रतिक्रिया को आकार देती हैं; पर लाभ मिलना अपने–आप विश्वास में नहीं बदलता। तीसरा, बिहार में, जहाँ बहुआयामी निर्धनता अब भी देश में सबसे ऊँची है, योजनाएँ राज्य और नागरिक के बीच संपर्क का मुख्य माध्यम हैं; जिला–स्तर पर लाभार्थियों की राजनीतिक धारणाओं का अध्ययन शोध–प्रस्ताव में एक अंतराल के रूप में चिह्नित है। लेख के अंत में शोध–प्रबंध की चार परिकल्पनाओं से जुड़ी विचारणीय प्रस्थापनाएँ दी गई हैं।

शब्दकोशः *कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक विश्वास, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, नीति–प्रतिपुष्टि, बिहार, नालंदा।*

प्रस्तावना

सार्वजनिक कल्याण योजनाएँ आज राज्य और नागरिक के बीच संपर्क का सबसे नियमित बिंदु हैं। राशन की दुकान, गैस कनेक्शन, मकान की किस्त या खाते में आया पैसा, इन्हीं अनुभवों से आम व्यक्ति शासन की ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के बारे में अपनी राय बनाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में प्रश्न केवल यह नहीं रहा कि योजनाएँ गरीबी घटाती हैं या नहीं, बल्कि यह भी कि वे लाभार्थी के मन में सरकार के प्रति विश्वास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

भारत में इस प्रश्न का आकार बड़ा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों तक की पात्रता है, जिसमें से मार्च 2025 में राज्यों द्वारा 80.56 करोड़ को चिह्नित किया बताया गया (द वायर, 2025)। पीएम–किसान की 23वीं किस्त (20 जून 2026) में लगभग 9.44 करोड़ किसानों को

Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.

₹18,880 करोड़ अंतरित किए गए (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2026क)। इतने बड़े पैमाने की योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव केवल चुनावी व्यवहार तक सीमित नहीं माना जा सकता।

इस लेख के तीन उद्देश्य हैं। पहला, कल्याणकारी राज्य और राजनीतिक विश्वास की मुख्य अवधारणाओं को संक्षेप में रखना। दूसरा, भारत में कल्याण योजनाओं के विकास–क्रम और पाँच प्रमुख योजनाओं (मनरेगा, पीएम–किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उज्ज्वला) की स्थिति को उपलब्ध आँकड़ों के साथ वर्णित करना। तीसरा, बिहार और नालंदा के संदर्भ को इस चित्र में रखकर शोध–प्रबंध की परिकल्पनाओं तक पहुँचने वाले सूत्र निकालना।

अध्ययन की सीमा। यह लेख शोध–प्रबंध के अध्याय–3 ('भारत में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं का विकास एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य') की भूमिका निभाता है। इसका सैद्धांतिक ढाँचा राष्ट्रीय है, जबकि अनुभवजन्य संदर्भ शोध–प्रस्ताव के अनुसार नालंदा जिले तक सीमित है। लेख वर्णनात्मक है और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैरू शोध–पत्र, संसदीय उत्तर, च्ठ की सामग्री और छप्ज् आयोग की रिपोर्ट।

सैद्धांतिक ढाँचाः कल्याणकारी राज्य और राजनीतिक विश्वास

कल्याणकारी राज्य। एस्पिंग–एंडरसन (1990) ने अठारह विकसित देशों के आधार पर कल्याणकारी राज्यों को उदार, रूढ़िवादी और सामाजिक–लोकतांत्रिक, इन तीन 'व्यवस्थाओं' में बाँटा और 'विवस्तुकरण' की कसौटी दी, यानी व्यक्ति का जीवन–निर्वाह किस हद तक बाज़ार पर निर्भर नहीं रहता। यह वर्गीकरण भारत पर सीधे लागू नहीं होता, क्योंकि इसकी रचना विकसित औद्योगिक देशों के लिए हुई थी; पर यह समझने में उपयोगी है कि कल्याण नीतियाँ केवल खर्च नहीं, नागरिकों के बीच संबंधों की एक संरचना भी बनाती हैं। भारतीय संदर्भ में द्रेज़ और सेन (2013) का तर्क है कि देश की मुख्य समस्या गरीबों और विशेषतः महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं पर कम ध्यान है। उनकी पुस्तक में 'जवाबदेही और भ्रष्टाचार' तथा 'निर्धनता और सामाजिक सहायता' पर अलग अध्याय हैं, जो संकेत देते हैं कि योजनाओं का मूल्यांकन उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही से अलग नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक विश्वास। अलमंड और वर्बा (1963) ने पाँच देशों में पाँच हज़ार से अधिक लोगों के साक्षात्कार के आधार पर 'नागरिक संस्कृति' की अवधारणा दी और राजनीतिक रुझानों को सहभागी, प्रजाजन–सदृश और संकीर्ण रूपों में बाँटा। ईस्टन (1975) ने राजनीतिक समर्थन को 'विशिष्ट' और 'विसरित' दो रूपों में अलग किया। विशिष्ट समर्थन सत्ता–धारकों के कार्यों और उनके परिणामों से मिलने वाली संतुष्टि से जुड़ा है, जबकि विसरित समर्थन पदों, संस्थाओं और व्यवस्था के प्रति अपेक्षाकृत स्थायी लगाव है। यह भेद इस शोध के लिए महत्त्वपूर्ण है। कोई लाभार्थी राशन या मकान की किस्त समय पर मिलने से किसी सरकार से संतुष्ट हो सकता है (विशिष्ट समर्थन), पर इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उसका विश्वास (विसरित समर्थन) बढ़ा है। लेवी और स्टोकर (2000) ने भी राजनीतिक विश्वास और 'विश्वसनीयता' के बीच अंतर पर बल दिया है। यानी प्रश्न यह भी है कि सरकार वास्तव में भरोसे के योग्य व्यवहार करती है या नहीं और नागरिक उसे कैसा पाते हैं।

नीति–प्रतिपुष्टि। दोनों धाराओं को जोड़ने वाला सिद्धांत 'नीति–प्रतिपुष्टि' है। पियर्सन (1993) ने तर्क दिया कि नीतियाँ केवल राजनीति का परिणाम नहीं, उसका कारण भी बन सकती हैं। मेटलर और सॉस (2004) ने इस विचार को नागरिकता तक बढ़ाया और बताया कि नीतियाँ सदस्यता की परिभाषा, राजनीतिक सामंजस्य या समूह–विभाजन, नागरिक क्षमताओं, नीति–एजेंडा और मूल्यांकन के ढाँचे तथा राजनीतिक सहभागिता को आकार दे सकती हैं। इस शोध के लिए निष्कर्ष यह है कि लाभार्थी का अनुभव, यानी योजना कैसे मिली, कितनी नियमित रही और किसने दी, राजनीतिक धारणा का स्रोत है; पर परिणाम सकारात्मक ही होगा, यह पहले से तय नहीं है।

भारत में कल्याण योजनाओं का ऐतिहासिक विकास

भारत में कल्याण–नीति का वैचारिक आधार संविधान के भाग–4 (राज्य के नीति–निदेशक तत्व) में है, जो राज्य से सामाजिक–आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा रखता है। विकास–क्रम को चार चरणों में समझा जा सकता है; यह विभाजन विश्लेषणात्मक है, कालक्रम की कठोर सीमा नहीं।

- **पहला चरणः** अधिकार–आधारित मोड़ (2005–2013)। मनरेगा (2005) ने ग्रामीण परिवारों को वैधानिक रोज़गार–गारंटी दी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ, जिसे आधिकारिक पोर्टल कल्याण–आधारित से अधिकार–आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव बताता है (एनएफएसए पोर्टल, उपलब्ध तिथि नहीं)। इस चरण में योजनाओं के साथ पात्रता और शिकायत–निवारण का कानूनी ढाँचा जुड़ा।
- **दूसरा चरणः** प्रौद्योगिकी और प्रत्यक्ष अंतरण (2013 के बाद)। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज) 1 जनवरी 2013 को आरंभ हुआ (मनोरमा ईयरबुक, 2025) और आगे चलकर 320 योजनाओं तक पहुँचा; आकाशवाणी के अनुसार अगस्त 2026 तक इसके माध्यम से 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक अंतरित हो चुके थे (प्रसार भारती, 2026)। आधार, जन–धन और मोबाइल पर आधारित भुगतान–ढाँचे ने योजनाओं की डिलीवरी का स्वरूप बदला।
- **तीसरा चरणः** केंद्र–ब्रांडेड योजनाएँ और श्रेय का केंद्रीकरण (2014 के बाद)। उज्ज्वला (1 मई 2016), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और पीएम–किसान (2019) जैसी योजनाएँ केंद्र के नाम से जुड़ीं। 2019 के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण में देशपांडे, टिलिन और कैलाश (2019) ने पाया कि पहले के चुनावों की तुलना में मतदाता कल्याण योजनाओं का श्रेय राज्य सरकारों या स्थानीय नेताओं के बजाय केंद्र सरकार को अधिक देने लगे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएँ अब भी राज्य सरकारों से अधिक जुड़ी रहीं।
- **चौथा चरणः** पुनर्संरचना (2025–26)। संसद ने दिसंबर 2025 में विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), अर्थात टठ–ळ ट।ड ळ अधिनियम पारित किया; यह 18 दिसंबर को पारित हुआ और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली (मोंगाबे इंडिया, 2025)। अधिनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और वैधानिक रोज़गार–गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2026ख)। रिपोर्टों के अनुसार विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और वित्तीय बोझ के प्रश्न पर विरोध किया (द स्टेट्समैन, 2025)। इस प्रकार मनरेगा अब एक पूर्ववर्ती योजना है, और इस अध्ययन में लाभार्थियों के मनरेगा–अनुभव को 2025–26 तक की अवधि के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

प्रमुख योजनाएँः स्वरूप, विस्तार और आँकड़े

अध्ययन की पाँच योजनाओं की राष्ट्रीय स्थिति निम्न तालिका में है।

योजना	आधार / आरंभ	राष्ट्रीय स्थिति
मनरेगा	अधिनियम 2005 (VB-G RAM G अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित (1 जुलाई 2026 से)	2024–25: 15.99 करोड़ पंजीकृत परिवार, 290.60 करोड़ श्रम–दिवस (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025क)
पीएम–किसान	फरवरी 2019	23वीं किस्त (20 जून 2026): ₹18,880 करोड़, 9. 44 करोड़ किसान (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2026 क)
पीएमएवाई–ग्रामीण	2016–17 से स्वीकृतियाँ	अगस्त 2025रू 3.84 करोड़ मकान स्वीकृत, 2.82 करोड़ पूर्ण (लोक सभा, 2025 क)
खाद्य सुरक्षा अधिनियम / सार्वजनिक वितरण प्रणाली	5 जुलाई 2013	अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्ति (मार्च 2025 में 80. 56 करोड़ चिह्नित (द वायर, 2025)
उज्ज्वला योजना	1 मई 2016	1 जनवरी 2025 तक 10.33 करोड़ कनेक्शन (data.gov.in, 2025)

मनरेगा। PIB के अनुसार 2024–25 में महिलाओं की भागीदारी 58.15% रही (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025d)। नागरिक–समाज संगठन लिबटेक इंडिया के ट्रैकर ने उसी वर्ष पंजीकृत परिवारों में 8.6% वृद्धि के बावजूद श्रम–दिवसों में 7.1% की गिरावट (288.83 करोड़ से 268.44 करोड़) और लगभग 7% परिवारों द्वारा 100 दिन पूरे करने की बात दर्ज की (लिबटेक इंडिया, 2025)।

पीएम–किसान। 23वीं किस्त में 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान शामिल थीं, और दिसंबर 2025 तक अपात्र लाभार्थियों से ₹416.75 करोड़ की वसूली की गई (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2026क)। यह वसूली संकेत देती है कि पात्रता–निर्धारण स्वयं राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया है।

बिहार के आँकड़े। बिहार में 7 अगस्त 2025 तक पीएम–किसान के अंतर्गत 2025–26 में 73.88 लाख पात्र किसानों को सहायता मिली और उज्ज्वला के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 तक ग्रामीण महिलाओं को 1.16 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित हुए (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025ख)। पीएमएवाई–ग्रामीण में 7 अगस्त 2025 तक लगभग 50.13 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 49.03 लाख मकान स्वीकृत और 38.43 लाख पूर्ण हुए (लोक सभा, 2025ख); स्वीकृति और पूर्णता के बीच लगभग 10.6 लाख मकानों का अंतर है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार में लगभग 8.71 करोड़ लाभार्थी दर्ज हैं (राज्य सभा, 2021)।

ये आँकड़े पहुँच के पैमाने को दर्शाते हैं, लाभार्थी के अनुभव को नहीं; अनुभव और धारणा का मापन प्राथमिक सर्वेक्षण का विषय है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और राज्य–नागरिक संबंध

DBT का तर्क है कि लाभ सीधे खाते में पहुँचे तो बिचौलियों की भूमिका घटेगी और नागरिक राज्य को अधिक पारदर्शी मानेगा। BlueKraft Digital Foundation के आकलन के अनुसार, जिसे PIB ने प्रकाशित किया, DBT से संचयी बचत ₹3.48 लाख करोड़ रही और लाभार्थी–कवरेज 11 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ हुआ (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2025ग)।

स्वतंत्र अनुभवजन्य प्रमाण अधिक सूक्ष्म चित्र देते हैं। आंध्र प्रदेश के 157 उप–जिलों और लगभग 1.9 करोड़ लोगों पर यादृच्छिक प्रयोग में मुरलीधरन, नीहौस और सुखटंकर (2016) ने पाया कि बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड से NREGS का भुगतान तेज़, अधिक पूर्वानुमेय और कम भ्रष्ट हुआ, कार्यक्रम तक पहुँच पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, और लाभार्थियों ने नई प्रणाली को भारी बहुमत से पसंद किया। बिहार में मनरेगा के 'जस्ट–इन–टाइम' भुगतान सुधार पर बनर्जी, डुफ़्लो, इम्बर्ट, मैथ्यू और पांडे (2020) ने पाया कि कार्यक्रम–व्यय 24% घटा जबकि रोज़गार थोड़ा बढ़ा, अभिलेखों में फ़र्ज़ी परिवार कम हुए और अधिकारियों की निजी संपत्ति 10% घटी; किंतु भुगतान में देरी बढ़ी। राष्ट्रीय विस्तार के बाद व्यय में स्थायी 19% की कमी दर्ज हुई। राजनीतिक अर्थ यह है कि 'रिसाव में कमी' और 'लाभार्थी का अनुभव' दो भिन्न बातें हो सकती हैं जो सुधार सरकारी कोष बचाता है, वह लाभार्थी के लिए देरी भी पैदा कर सकता है।

ये अध्ययन राजनीतिक विश्वास को सीधे नहीं मापते। इसी कारण ऐसे प्रशासनिक सुधारों के बाद लाभार्थी की धारणा, अर्थात समयबद्धता, निष्पक्षता और श्रेय के बोध, का नालंदा जैसे जिले में ज़मीनी अध्ययन आवश्यक है। बिहार का साइकिल कार्यक्रम (2006) दृश्यता और श्रेय के प्रश्न का उदाहरण है। मुरलीधरन और प्रकाश (2017) के अनुसार इससे लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में नामांकन में लगभग 32% की वृद्धि और लैंगिक अंतर में 40% की कमी आई। एक साक्षात्कार में मुरलीधरन ने बताया कि साइकिल की राशि सार्वजनिक समारोहों में बाँटी गई थी, जिनसे सरकार राजनीतिक लाभ की अपेक्षा रखती थी (अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, 2017)। अर्थात नीति के प्रभाव के साथ उसकी राजनीतिक दृश्यता भी नीति–रचना का हिस्सा रही है।

बिहार और नालंदाः क्षेत्रीय संदर्भ

बिहार। NITI आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (2023) के अनुसार बिहार में 2019–21 में 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से निर्धन थी, जो देश में सर्वाधिक है; 2015–16 के 51.89% से यह 18.13

प्रतिशत–अंक नीचे आया, जो राज्यों में सबसे बड़ी गिरावट थी (यूएनडीपी, 2023)। रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली जैसे सूचकों में सुधार ने निर्धनता घटाने में भूमिका निभाई (द ट्रिब्यून, 2023)। निर्धनता में तीव्र गिरावट और उसका अब भी सर्वोच्च स्तर, दोनों तथ्यों के बीच बिहार में कल्याण योजनाओं की भूमिका पढ़ी जानी चाहिए।

राजनीतिक संदर्भ। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव योजनाओं और मतदान के संबंध पर चल रही बहस का ताज़ा उदाहरण है। राजग (NDA) ने 243 में से 202 सीटें जीतीं (डेक्कन हेराल्ड, 2025क)। चुनाव से पहले आरंभ मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना में 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को ₹10,000 प्रति महिला अंतरित किए गए (करियर्स 360, 2025); बाद की रिपोर्टों में 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक राशि पहुँचने की बात कही गई (डेक्कन हेराल्ड, 2025ख)। प्रेक्षकों ने महिलाओं के ऊँचे मतदान, जो स्रोत के अनुसार पुरुषों से 8.8 प्रतिशत अधिक रहा, को इन योजनाओं से जोड़ा (डाउन टू अर्थ, 2025), जबकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक धन से मत 'खरीदे' गए (डेक्कन हेराल्ड, 2025ग)। ये दोनों व्याख्याएँ प्रेक्षकों और राजनेताओं के दावे हैं, किसी सर्वेक्षण–आधारित कारण–विश्लेषण के परिणाम नहीं; इसलिए लाभार्थियों की धारणाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन महत्त्व रखता है।

नालंदा। 2011 की जनगणना के अनुसार नालंदा की जनसंख्या 28,77,653 थी, जिसमें 24,19,759 (लगभग 84%) ग्रामीण और 4,57,894 शहरी थे; अनुसूचित जाति की जनसंख्या 6,07,672 (लगभग 21%) थी (सिटीपॉपुलेशन, उपलब्ध तिथि नहीं)। जिले में 6 कस्बे और 1,055 गाँव हैं और 2011 में साक्षरता दर 64.43% थी (इंडियास्टैट, उपलब्ध तिथि नहीं)। ग्रामीण–प्रधान संरचना और अनुसूचित जाति की उल्लेखनीय उपस्थिति इसे योजनाओं की पहुँच और धारणाओं के अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनाती है।

कल्याण योजनाएँ और राजनीतिक विश्वासः उपलब्ध साहित्य का विवेचन

भारतीय साहित्य में योजनाओं और राजनीतिक व्यवहार के संबंध का अध्ययन मुख्यतः चुनावी व्यवहार और श्रेय–निर्धारण के माध्यम से हुआ है। इस साहित्य से चार प्रवृत्तियाँ उभरती हैं।

- पहलीः कल्याण–राजनीति में राज्य की भूमिका। टिलिन, देशपांडे और कैलाश (2015) द्वारा संपादित संग्रह 'पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरः कंपेरिज़न्स अक्रॉस इंडियन स्टेट्स' भारतीय राज्यों की तुलना के माध्यम से कल्याण–नीति के निर्माण में राज्यों की अपनी भूमिका की ओर ध्यान दिलाता है। इसका अर्थ यह है कि कल्याण योजनाओं के राजनीतिक प्रभाव राज्य–विशेष की संस्थागत और राजनीतिक परिस्थितियों से बँधे होते हैं। बिहार या नालंदा के निष्कर्ष इसलिए स्वतः अन्य राज्यों पर लागू नहीं किए जा सकते, और यही बात शोध–प्रस्ताव की इस स्वीकृति से मेल खाती है कि अध्ययन एक जिले तक सीमित है।
- दूसरीः श्रेय का केंद्रीकरण और योजना–वार भिन्नता। देशपांडे, टिलिन और कैलाश (2019) के अनुसार 2019 में केंद्र सरकार को श्रेय देने की प्रवृत्ति पहले की तुलना में बढ़ी, विशेषतः उज्ज्वला और जन–धन जैसी नई योजनाओं के संदर्भ में। अखिल–भारतीय स्तर पर उज्ज्वला, जन–धन या आवास योजना के लाभार्थियों में भाजपा को वोट देने की संभावना के कुछ प्रमाण मिले, जबकि पेंशन या मनरेगा के लाभार्थियों में यह संभावना कम थी। इस निष्कर्ष का महत्त्व यह है कि 'लाभार्थी' एक समरूप श्रेणी नहीं है; योजना का स्वरूप, उसकी दृश्यता और उसे किस सरकार से जोड़ा जाता है, ये सब राजनीतिक प्रतिक्रिया को बदल देते हैं।
- तीसरीः पहुँच और 'विवेकशील' मतदाता। कैलाश (2024) राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2024 के आँकड़ों के आधार पर यह प्रश्न उठाते हैं कि कल्याण–वितरण पर व्यापक प्रचार के बावजूद 2024 में भाजपा अपना पिछला मत–प्रतिशत क्यों नहीं बचा सकी। उनका निष्कर्ष है कि मतदाता विवेकशील हैं और कल्याण–वितरण में पहुँच की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। इस दृष्टि से योजना का अस्तित्व और योजना का सहज रूप से मिलना दो भिन्न बातें हैं, और राजनीतिक विश्वास का निर्माण संभवतः

दूसरी पर अधिक निर्भर करता है। यह इस शोध की परिकल्पना–2 (समयबद्धता और निष्पक्षता) की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि बनाता है।

- चौथीः प्रशासनिक क्षमता और रिसाव। द्रेज़ और सेन (2013) का जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर ज़ोर तथा स्मार्टकार्ड और जस्ट–इन–टाइम भुगतान पर किए गए अध्ययन (मुरलीधरन आदि, 2016; बनर्जी आदि, 2020) यह दिखाते हैं कि भुगतान की गति, पारदर्शिता और रिसाव मापे जा सकने वाले तत्त्व हैं। नागरिक के अनुभव में यही तत्त्व 'ईमानदार और कुशल सरकार' की छवि का आधार बनते हैं।

अंतराल। उपर्युक्त अध्ययन मुख्यतः मतदान, श्रेय–निर्धारण या प्रशासनिक रिसाव पर केंद्रित हैं। राजनीतिक विश्वास को लाभार्थी की अपनी धारणा के रूप में, सरकार, संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति अलग–अलग, जिला–स्तर पर मापने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत कम हैं। ईस्टन के विशिष्ट और विसरित समर्थन के भेद (ईस्टन, 1975) तथा नीति–प्रतिपुष्टि के सिद्धांत (पियर्सन, 1993; मेटलर और सॉस, 2004) को जोड़कर नालंदा में लाभार्थियों की धारणाओं का अध्ययन यही अंतराल भरने का प्रयास है।

विवेचना, सीमाएँ और निष्कर्ष

शोध–परिकल्पनाओं से संबंध। उपर्युक्त विवेचन से शोध–प्रबंध की चार परिकल्पनाओं से जुड़ी प्रस्थापनाएँ निकलती हैं। ये निष्कर्ष नहीं, अनुभवजन्य अध्ययन की दिशा तय करने वाले सूत्र हैं।

- परिकल्पना–1 (क्रियान्वयन और विश्वास): नीति–प्रतिपुष्टि सिद्धांत (पियर्सन, 1993; मेटलर और सॉस, 2004) के अनुसार लाभार्थी का अनुभव राजनीतिक धारणा को आकार देता है, पर ईस्टन (1975) का भेद बताता है कि इसका प्रभाव पहले विशिष्ट समर्थन, अर्थात सरकार के कार्यों के प्रति संतुष्टि, में दिखेगा। अतः विश्वास को सरकार, राजनीतिक संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अलग–अलग मापना उपयुक्त है।
- परिकल्पना–2 (समयबद्धता, निष्पक्षता और विश्वास): रिसाव घटाने वाले सुधारों में भी भुगतान–देरी बढ़ सकती है (बनर्जी आदि, 2020), और पहुँच की समस्याएँ मतदाता के आकलन को प्रभावित करती हैं (कैलाश, 2024)। इसलिए 'समय पर मिलना' और 'बिना भेदभाव मिलना' को अलग–अलग चरों के रूप में लिया जाए।
- परिकल्पना–3 (योजना–विफलता और अविश्वास): पीएमएवाई–ग्रामीण में बिहार की स्वीकृति और पूर्णता के बीच लगभग 10.6 लाख मकानों का अंतर तथा मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों का लगभग 7% अनुपात (लिबटेक इंडिया, 2025) ऐसे संकेतक हैं जिनके आधार पर 'विफलता' के अनुभव को परखा जा सकता है।
- परिकल्पना–4 (कल्याण योजनाएँ और राजनीतिक सहभागिता): श्रेय–निर्धारण के साहित्य (देशपांडे, टिलिन और कैलाश, 2019; कैलाश, 2024) के अनुसार लाभ और राजनीतिक व्यवहार का संबंध योजना–विशेष और संदर्भ–विशेष है। इसलिए लाभार्थी और गैर–लाभार्थी की तुलना कुल योजनाओं के बजाय योजना–वार की जानी चाहिए।

पद्धतिगत संकेत। पहला, मनरेगा के स्थान पर VB-G RAM G आने से लाभार्थियों के अनुभव में दो व्यवस्थाओं का मिश्रण संभव है; प्रश्नावली में अनुभव की अवधि स्पष्ट की जाए। दूसरा, श्रेय–निर्धारण (केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रतिनिधि) को अलग प्रश्न के रूप में रखा जाए, क्योंकि साहित्य में यही कारक प्रतिक्रिया बदलता है। तीसरा, समयबद्धता की धारणा को वास्तविक विलंब के रिकॉर्ड (जैसे किस्त की तिथि) से मिलाकर परखा जाए।

सीमाएँ। लेख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और उसमें प्रयुक्त आँकड़े अलग–अलग तिथियों के हैं। अनेक स्रोत सरकारी हैं और अपने कार्यक्रम का स्वयं आकलन करते हैं; DBT–बचत का आँकड़ा इसी श्रेणी में है। बिहार–2025 के चुनाव और योजना–अंतरण के संबंध पर उपलब्ध सामग्री मुख्यतः प्रेक्षकों की टिप्पणी है, अकादमिक कारण–विश्लेषण नहीं।

निष्कर्ष। भारत में कल्याण योजनाएँ अधिकार–आधारित कानूनों से डिजिटल और केंद्र–ब्रांडेड रूप तक और अब पुनर्संरचित ढाँचे तक पहुँची हैं। सिद्धांत और उपलब्ध प्रमाण दोनों संकेत देते हैं कि लाभार्थी का अनुभव राजनीतिक धारणा को प्रभावित करता है, पर प्रभाव की दिशा और गहराई पहुँच, समयबद्धता, श्रेय और संदर्भ पर निर्भर है। बिहार, जहाँ निर्धनता में तीव्र गिरावट के बावजूद उसका स्तर देश में सर्वाधिक है, इस प्रश्न का महत्त्वपूर्ण परीक्षण–क्षेत्र है। नालंदा में लाभार्थियों की धारणाओं का ज़मीनी अध्ययन ही यह स्पष्ट कर सकेगा कि योजनाओं ने राजनीतिक विश्वास को किस सीमा तक और किस दिशा में प्रभावित किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलमंड, जी. ए. एवं वर्बा, एस. (1963). द सिविक कल्चरः पॉलिटिकल एटिट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस (The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations). प्रिंसटन, एन. जे.रू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. बनर्जी, ए., डुफ़्लो, ई., इम्बर्ट, सी., मैथ्यू, एस. एवं पांडे, आर. (2020). ई–गवर्नेंस, जवाबदेही और सार्वजनिक कार्यक्रमों में रिसावरू भारत में वित्तीय प्रबंधन सुधार के प्रायोगिक प्रमाण (E-governance] accountability] and leakage in public programs). अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नलः एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 12(4), 39–72. https://doi-org/10-1257/app-20180302
3. सिटीपॉपुलेशन (उपलब्ध तिथि नहीं). नालंदा जिला, बिहारः जनगणना 2011 जनसंख्या तालिकाएँ (Nalanda district: Census 2011). https://citypopulation-de/en/india/bihar/admin/229&&nalanda/
4. data.gov.in (2025). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 01–01–2025 तक जारी कनेक्शनों की राज्यध्संघ राज्यक्षेत्र–वार संख्या (स्रोतः राज्य सभा). https://community-data-gov-in/\p.119318
5. देशपांडे, आर., टिलिन, एल. एवं कैलाश, के. के. (2019). भाजपा की कल्याण योजनाएँः क्या 2019 के चुनावों में उनसे फ़र्क पड़ा? (The BJP's welfare schemes: Did they make a difference in the 2019 elections\). स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स, 7(2), 219–233. https://doi-org/10-1177/2321023019874911
6. द्रेज़, जे. एवं सेन, ए. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरीरू इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस (An Uncertain Glory: India and Its Contradictions). प्रिंसटन, एन.जे.ः प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. ईस्टन, डी. (1975). राजनीतिक समर्थन की अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन (A re-assessment of the concept of political support). ब्रिटिश जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 5(4), 435–457.
8. एस्पिंग–एंडरसन, जी. (1990). द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज़्म (The Three Worlds of Welfare Capitalism). कैम्ब्रिजरू पॉलिटी प्रेस।
9. कैलाश, के. के. (2024). सामाजिक कल्याण की राजनीति' भाजपा और विवेकशील मतदाता (The politics of social welfare: The BJP and the discerning voter). स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स, 12(2), 228–250. https://doi-org/10-1177/23210230241291220
10. लेवी, एम. एवं स्टोकर, एल. (2000). राजनीतिक विश्वास और विश्वसनीयता (Political trust and trustworthiness). एनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 3, 475–507.
11. लिबटेक इंडिया (2025). लिबटेक इंडिया ट्रैकर वित्त वर्ष 2024–25 (LibTech India Tracker FY 2024–25). https://libtech-in/wp&content/uploads/2025/05/LibTech-India-Tracker-FY-2024-25-English-pdf
12. लोक सभा (2025क). अतारांकित प्रश्न संख्या 3744, 12 अगस्त 2025 को उत्तरित (पीएमएवाई–ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित मकान). https://eparlib-sansad-in/bitstream/123456789/2995490/1/AU3744-yZJWba-pdf

13. लोक सभा (2025ख). पीएमएवाई–ग्रामीणः 07.08.2025 तक संचयी लक्ष्य, स्वीकृत और पूर्ण मकानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण (अतारांकित प्रश्न संख्या 3722). https://eparlib-sansad-in/bitstream/123456789/2995468/1/AU3722&13vkmB-pdf
14. मेटलर, एस. एवं सॉस, जे. (2004). लोकतांत्रिक नागरिकता पर सार्वजनिक नीति के परिणामरू नीति–अध्ययन और जन–राजनीति के बीच सेतु (The consequences of public policy for democratic citizenship). पर्स्पेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स, 2(1), 55–73.
15. मुरलीधरन, के., नीहौस, पी. एवं सुखटंकर, एस. (2016). राज्य–क्षमता का निर्माणरू भारत में बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड के प्रमाण (Building state capacity: Evidence from biometric smartcards in Indi). अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 106(10), 2895–2929. https://doi-org/10-1257/aer-20141346
16. मुरलीधरन, के. एवं प्रकाश, एन. (2017). स्कूल के लिए साइकिलरू भारत में लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय नामांकन में वृद्धि (Cycling to school). अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नलः एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 9(3), 321–350. https://doi-org/10-1257/app-20160004
17. एनएफएसए पोर्टल (उपलब्ध तिथि नहीं). हमारे बारे में. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग. https://nfsa-gov-in/portal/AboutUs
18. पियर्सन, पी. (1993). जब परिणाम कारण बन जाता हैरू नीति–प्रतिपुष्टि और राजनीतिक परिवर्तन (When effect becomes cause). वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 45(4), 595–628.
19. प्रेस सूचना ब्यूरो (2025क, अगस्त). मनरेगारू परिवार और सृजित श्रम–दिवस, वित्त वर्ष 2024–25. https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc2025826620001-pdf
20. प्रेस सूचना ब्यूरो (2025ख, सितंबर). बिहार में केंद्र सरकार की पहलें. https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc2025912633901-pdf
21. प्रेस सूचना ब्यूरो (2025ग, 21 अप्रैल). भारत का क्ठज्रू कल्याण–दक्षता में वृद्धि (India's DBT: Boosting welfare efficiency). https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/apr/doc2025421543301-pdf
22- प्रेस सूचना ब्यूरो (2026क, 20 जून). पीएम–किसान की 23वीं किस्त. https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jun/doc2026620898101-pdf
23. प्रेस सूचना ब्यूरो (2026ख, मई). वीबी–जी राम जी अधिनियम, 2025. https://static-pib-gov-in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/may/doc2026511867601-pdf
24. राज्य सभा (2021). अतारांकित प्रश्न संख्या 2789, 19 मार्च 2021 को उत्तरित (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड). https://rsdebate-nic-in/bitstream/123456789/716812/1/PQ&253&19032021&U2789&p328& p330-pdf
25. द वायर (2025, 25 मार्च). 79 लाख लोगों को अभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ़्त राशन नहीं मिला (79 lakh yet to receive free rations under NFSA). https://thewire-in/government/79-lakh-yet-to-receive-free-rations-nfsa
26. टिलिन, एल., देशपांडे, आर. एवं कैलाश, के. के. (संपा.) (2015). पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरः कंपेरिज़न्स अक्रॉस इंडियन स्टेट्स (Politics of Welfare: Comparisons across Indian States). नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
27. यूएनडीपी (2023). राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांकः प्रगति समीक्षा 2023 (नीति आयोग) (National Multidimensional Poverty IndeÛ: A Progress Review 2023). https://www-undp-org/node/420786.

❑❑❑